FOR IMMEDIATE RELEASE

The World Bank

Contacts: *In Delhi*
Sumir Lal (91 11) 2461-7241
slal@worldbank.org
In Washington
Dale Lautenbach (202) 473-3405
dlautenbach@worldbank.org

विश्व बैंक ने भारतीय शहरी पविहन की मुख्य पहल के लिए सहायता को स्थगित किया

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 2 मार्च, 2006 – विश्व बैंक ने मुंबई शहरी परिवहन परियोजना (MUTP) द्वारा प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के साथ साम्यिक व्यवहार से जुड़ी चिंताओं का निवारण होने तक इस परियोजना के सड़क और पुनर्स्थापन घटकों के लिए वित्तीय सहायता को अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया है।

MUTP एक उच्चाकांक्षी सड़क एवं रेल नवीकरण योजना है जिसमें 17,000 से अधिक परिवारों और लगभग 2,500 व्यावसायिक स्थापनाओं का अस्वैच्छिक पुनर्स्थापन अंतर्ग्रस्त है। लगभग 14,000 परिवार सुरक्षित आवासों में पहले ही जा चुके हैं। ये लोग इस शहर के सबसे गरीब लोगों से थे और उनमें से अधिकांश लोग हॉंगर जैसी एवं खतरनाक स्थितियों में रेल लाइनों के नजदीक रह रहे थे।

अब वे ऊँची इमारतों में बस गए हैं जहां उन्हें धारण–अधिकार की सुरक्षा प्रदान की जाएगीं, और सर्वेक्षणों ने दर्शाया है कि उनमें से अधिकांश लोग अपनी बेहतर स्थिति से मोटे तौर पर संतुष्ट हैं। इसके अलावा रेल प्रणाली की कुशलता में सुधार हुआ है जिससे लाखों मुंबई निवासियों के लिए दैनिक यात्रा आसान बनी है।

बहरहाल, इस जटिल परियोजना के क्रियान्वयन के पहलुओं के साथ कठिनाइयां भी आई हैं जो पूरी तरह से 1 करोड़ 30 लाख लोगों के शहर ओर विश्व के एक सर्वाधिक भीड़भाड़ वाले महानरीय क्षेत्र में घटित हो रहा है। कुछ परिवारों के पुनर्स्थापन के बारे में, जो महाराष्ट्र राज्य सरकार और बैंक के बीच हुए समझौते के अनुसार नहीं किया गया है, गंभीर समस्याएं पैदा हुई हैं।

बहरहाल, इनमें से अनेक परिवारों को पुनर्स्थापन पश्चात की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जैसे जल और कूड़ा हटाए जाने जैसी सेवाओं की अनिश्चितता। कुछ परिवारों को रोजमर्रा की यात्रा के लिए अधिक समय से जूझना पड़ रहा है और इमारतों के रखरखाव के लिए अनुरक्षण निधियों के अंतरण में देरी हुई है। इसके अलावा, क्षतिपूर्ति की मांग कर रहे व्यक्तियों के लिए शिकायत प्रणाली सही प्रकार से कार्य नहीं कर रही है।

श्री माइकल कार्टर, नई दिल्ली में भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर के शब्दों में, "स्थगन एक गंभीर कदम है जो यह दर्शाता है कि इन मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान किए जाने के प्रति हम कितने गंभीर हैं। महाराष्ट्र सरकार के पास मौजूदा समस्याओं का निवारण करने और यह सुनिश्चित करने कि बाकी पुनर्स्थापन हमारे समझौतों के अनुसार किया जाए, दोनों के लिए एक व्यावहारिक योजना है। अब मुख्य बात उसका क्रियान्वयन है। हम प्रभावित लोगों के लिए संतोषजनक समाधान सुनिश्चित करने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करने हेतु उनके साथ कार्य करते रहेंगे। कुछ प्रगति होने पर हम इस स्थगन की पुनरीक्षा करेंगे।"

उन्होंने कहा कि बैंक को विश्वास है कि इन मुद्दों का निवारण किया जा सकता है: "हमारी नीतियों और समझौतों के अनुसार इसको ठीक करने में सरकार की मदद करने की प्रक्रिया से हम एक पल भी अलग नहीं होंगे। कोई भी पीछे नहीं छूटना चाहिए, न तो दुकानदार और न ही परिवार।"

श्री कार्टर ने कहा, "भारत में शहरी चुनौती अत्यंत विशालकाय है। 2025 तक लगभग आधा खरब लोग इस देश के शहरों में निवास कर रहे होंगे जिससे विकास के नए अवसर और गरीबी की चुनौतियों, दोनों ही अत्यंत विकट रूप से सामने आएंगे। भारत सरकार ने अपने राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन में इसको स्वीकार किया है। दुर्भाग्यवश शहर के विकास के लिए कुछ पुनर्स्थापन अपरिहार्य है, और चुनौती है इसे एक ऐसी प्रक्रिया बनाना जो प्रभावित लोगों के भविष्य एवं जीवन स्तर में सुधार करे – वे लोग इसको उन्नति के एक अवसर के रूप में देखें।"

श्री कार्टर ने कहा, "विश्व बैंक को इस प्रकार के प्रभावों पर साम्यिक कार्रवाई करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य अपनी नीतियों पर गर्व है। जटिल और कठिन? बिल्कुल हां। लेकिन हम साथ नहीं छोड़ेंगे।"

940 मिलियन अमेरिकी डालर की मुंबई शहरी परिवहन परियोजना के सड़क एवं रेल घटकों के लिए 463 मिलियन अमेरिकी डालर के आई.बी.आर.डी. ऋण और पुनर्स्थापन के लिए 79 मिलियन अमेरिकी डालन के आई.डी.ए. ऋण की सहायता प्राप्त है। आई.डी.ए. ऋण और ऋण के सड़क घटक (150 मिलियन अमेरिकी डालर) का वितरण उपर्युक्त मुद्दों का समाधान होने तक स्थगित कर दिया गया है।

आई.डी.ए. इंटरनेशनल डेवलेपमेंट एसोसिएशन है जो विश्व बैंक समूह का रियायती ऋण देने वाला अंग है और आई.बी.आर.डी. इंटरनेशन बैंक फॉर रिस्ट्रक्चनिंग एंड डेवलेपमेंट है जो बैंक का कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने वाला अंग है।

###